

न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

| | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| प्रकरण संख्या 062/2025(रा.प्रा.प.) (GCMS 2025/204) | दायर दिनांक 28.08.2025 | निर्णय दिनांक 18.02.2026 |
|--|---------------------------|-----------------------------|

अनवान

1. शंकरलाल पिता वरदीचन्द जाति धाकड़ आयु वयस्क, निवासी बांगेड़ा घाटा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-प्रार्थी

बनाम

1. बगदीराम पिता नानालाल जाति कुम्हार आयु वयस्क, निवासी बांगेड़ा घाटा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. राधा बाई पत्नी बगदीराम जाति कुम्हार आयु वयस्क, निवासी बांगेड़ा घाटा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3. सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :- श्री छोगालाल जाट
श्री खुमराज कुमावत
भैरूलाल सालवी

अधिवक्ता प्रार्थी
अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 व 2
राजकीय अभिभाषक

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत नियम 14(04) भू आवंटन नियम, 1970
विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा बमिसल क्रमांक
778/2021 आवंटन दिनांक 11.11.2021**

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी ने एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत राजस्थान भू-राजस्व (कृषि-प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(04) के अन्तर्गत विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 01 व 02 को मौजा बांगेड़ा घाटा, तहसील निम्बाहेड़ा की बिलानाम आराजी संख्या 1028 रकबा 0.30 है. व आराजी संख्या 1245 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि के संबंध में किया गया भू-आवंटन विधि, नियम एवं तथ्यों के विपरित होने से निरस्त योग्य



है। प्रार्थी का काफी पुराना कब्जा है जिसकी कोई जांच पडताल नहीं की। विपक्षी संख्या 01 व 02 का कब्जा नहीं होते हुए भूमि आवंटन करने में भूल की, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री खुमराज कुमावत ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। विपक्षी संख्या 03 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित रहे। अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा की भू आवंटन पत्रावली तलब की गई। पत्रावली प्राप्त होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि विपक्षी संख्या 01 व 02 के नाम पर मौजा बांगेड़ा घाटा, तहसील निम्बोड़ा की बिलानाम आराजी संख्या 1028 व आराजी संख्या 1245 में से रकबा क्रमशः 0.30 है. व रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि आवंटन किया गया है जो कि विपक्षी संख्या 03 की रिपोर्ट के आधार पर आवंटन का पात्र मानते हुए किया है जो कि अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। विपक्षी संख्या 01 व 02 बांगेड़ा घाटा के निवासी होकर विपक्षी संख्या 01 के नाम पर कुल रकबा 0.93 है. भूमि दर्ज रेकार्ड होना अंकित किया है विपक्षी संख्या 02 विपक्षी संख्या 01 की पत्नी होकर दोनों एक यूनिट है ऐसी स्थिति में विपक्षीगण आवंटन के पात्र ही नहीं थे। प्रश्नगत आराजीयात आवंटन करने से पूर्व कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई न ही आवंटन नियम 5, 6 व 7 की पालना की गई विवादित बिलानाम आराजीयात प्रार्थी की कृषि आराजीयात से लगी होकर प्रार्थी के कब्जे काशत में चली आ रही है। विवादित भूमि प्रार्थी के नियमन योग्य भूमि होते हुये भी उक्त आराजीयात विपक्षी संख्या 01 व 02 के आवंटन कर दी जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 01 व 02 के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

इस पर विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 व 02 ने कथन किया कि भू-आवंटन कमेटी द्वारा विपक्षीगण को आवंटन नियमों के अधीन किया गया है, जो किसी भी प्रकार से निरस्त नहीं किया जा सकता है, उक्त प्रकरण में भू-आवंटन में किसी प्रकार की धोखेबाजी व गलत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है तथा आवंटन विधि अनुसार किया गया है। प्रार्थी का आवंटित भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों को आधार बनाकर आवेदन पेश किया है। पटवारी रिपोर्ट में खाता संख्या 238 व 285 में जो भूमि अंकित की गई है उक्त भूमि, भूमिहीन की परिभाषा में आने से तथा आवंटन की पूरी पात्रता रखते हैं जिससे भू-आवंटन कमेटी ने नियमों की पूर्ण पालना करते हुए विपक्षीगण के पक्ष में आवंटन किया है। वक्त आवंटन उक्त आराजीयात मौके पर खाली भूमि



नहीं होकर विपक्षीगण के कब्जे-काश्त में चली आ रही थी व विपक्षीगण के विरुद्ध नियमित रूप से अतिक्रमण की कार्यवाही हुई है जिससे विपक्षीगण के पक्ष में पूर्णतया विधि-सम्मत तरीके से आवंटन हुआ है जो किसी भी प्रकार से निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन खारिज फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र के माध्यम से विधिक तथ्यों के संबंध में उच्च/एतराज किया जाकर प्रकरण में विधिक तथ्यों को उठाया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन पत्रावली भी प्राप्त हो चुकी है, अतः प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर फरमावें।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि विपक्षीगण सद्भावी कृषक नहीं है तथा न ही भूमिहीन है अतः आवंटन निरस्त योग्य है। इस प्रकार विधि के प्रतिकूल भूमि आवंटित की है। ग्रामवासियान को न तो आवंटन की सूचना दी गई न उनको सुना गया। आवंटित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई और ना ही उक्त आराजीयात के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। बिना जांच-पडताल के उक्त बिलानाम आराजीयात का विपक्षीगण को आवंटन आदेश पारित कर दिया है जो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 01 व 02 का आवंटन निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस का मनन किया। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 में कृषि योग्य भूमि के आवंटन की व्यवस्था की गई है कि :-

101. Allotment of land for agricultural purposes – (1) Save as otherwise provided elsewhere by this Act, lands for agricultural purposes shall be allotted by such authority and in such manner as may be prescribed by rules made by the State Government in this behalf.

(2) All allotment of land under this section shall be subject to the payment of rent fixed at such rates as may be fixed according to custom or by usage or any law on the subject.

(3) XXX delted XXX]

(4) If there be more than one person requiring the same land, the allotment shall be made in the following order –

- (i) to co-sharer of the holding if it forms part of a compact block or is irrigated from the same source, preference amongst such co-sharers being given to one having land less than the area prescribed by rules made under the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Rajasthan Act 3 of 1955);
- (ii) to persons residing in the village in which land be situated, preference amongst such persons being given to persons having no land or less than the area prescribed by the said rules;
- (iii) by drawing lots:]



Provided that the area so taken together with the area held by him does not exceed the area prescribed by the said rules.

14. Condition of Allotment. –

(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Office [or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules] either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:

Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.

अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट प्रतिवेदित है कि आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर अप्रार्थी संख्या 01 के हस्ताक्षर ही अंकित है अप्रार्थी संख्या 02 के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित नहीं है।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 7 के तहत आवंटन के लिये आवेदन-पत्र आमन्त्रित करने की उद्घोषणा जो कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 61 के प्रावधित रीति से प्ररूप-2 में पन्द्रह दिवसीय कालावधि हेतु जारी किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित है एवं उक्त राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों में आज्ञात्मक प्रावधान है जिनकी समुचित पालना किया जाना आवश्यक है, किन्तु इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई भी समुचित दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे उक्त आवंटन की पूर्ण प्रक्रिया दूषित होना प्रकट होता है। इस प्रकार हस्तगत आवंटन विधि अनुसार प्रावधित पूर्ण प्रक्रिया से नहीं किया जाना न्यायालय के समक्ष प्रमाणित पाया जाता है।

इसके साथ ही आवंटि को भूमि का कब्जा सिपुर्द किये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। भूमि आवंटन के संबंध में कब्जा सिपुर्दगी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि प्रकरण में यह तथ्य सर्वमान्य है कि उक्त आवंटन आराजी संख्या 1028 एवं आराजी संख्या 1245 में से विपक्षी संख्या 01 व 02 को आवंटित 0.30 व 0.50 हैक्टेयर भूमि के संबंध में कब्जा सिपुर्द किये जाने बाबत् पर्चा मौका कब्जा सिपुर्दगी महत्वपूर्ण ठोस दस्तावेजी साक्ष्य है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही आवंटित भूमि पर विपक्षीगण के कब्जा एवं आवंटन शर्तों की पालना के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य विपक्षीगण द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जहां तक आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होने का तथ्य प्रार्थी द्वारा उठाया गया है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई भी ऐसा ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह प्रमाणित हो की आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। यह तथ्य केवल मौखिक कथनों से स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। कब्जा बिना ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के प्रमाणित नहीं हो सकता है। इसके साथ ही यदि



कब्जा प्रार्थी का मान भी लिया जाये तो निश्चित तौर पर प्रार्थी अतिचारी की श्रेणी में है क्योंकि पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो की प्रार्थी द्वारा नियम 20 के तहत सक्षम स्तर पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही प्रार्थी का भी आवंटित भूमि पर कब्जा न्यायालय के समक्ष प्रमाणित नहीं पाया गया है।

हस्तगत प्रकरण में विपक्षीगण को भूमि का आवंटन विधिवत नहीं किया जाना प्रमाणित पाया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 778/2021 दिनांक 11.11.2021 में त्रुटि कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाता है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं विपक्षी संख्या 01 एवं 02 का आवंटन निरस्त जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत नियम 14(04) कृषि प्रयोजनार्थ भू-आवंटन नियम 1970 को स्वीकार किया जाता है एवं आवंटन सलाहकार समिति की राय एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा पारित आवंटन आदेश प्रकरण संख्या 778/2021 दिनांक 11.11.2021 का आवंटन निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 778/2021 में दिनांक 11.11.2021 से आवंटित भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज अंकित करे।
'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(आलोक रंजन)

